

नेहरू मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी कॉऑपरेटिव

सोसाइटी लिमिटेड, और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

(बी.पी. सिन्हा, सी.जे., पी.बी. गजेंद्रगढकर,

के.एन. वांचू, के.सी. दास गुप्ता और

जे.सी. शाह, जेजे.)

मोटर वाहन-योजना का प्रकाशन-योजना, यदि संवैधानिक रूप से वैध है-मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (1939 का 4), ए.एल. 65 सी, 68 डी(3) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास मेनि) नियम, 1960, आर 3 भारत का संविधान, अनुच्छेद, 14, 32।

याचिकाकर्ता जोधपुर-बिलाड़ा और बिलाड़ा-ब्यावर म्यूट पर स्टेज-कैरिज परमिट धारक थे। राजस्थान रोडवेज ने एक मसौदा योजना प्रकाशित की, जिसमें जोधपुर बिलाड़ा-ब्यावर-अजमेर मार्ग पर परिवहन सेवा को रोडवेज द्वारा अपने अधीन लेने और तीन ओवरलैपिंग मार्गों या उनके हिस्सों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जो पूरी तरह से जोधपुर बिलाड़ा-ब्यावर पर थे। अजमेर रोड और इन तीन ओवरलैपिंग मार्गों पर परमिट धारकों के नाम उनके परमिट के साथ रद्द करने के लिए निर्दिष्ट किए गए थे और किसी भी अन्य परिवहन वाहन को उस मार्ग पर नहीं चलना था जिसे लिया जाना था। याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज की और लीगल रिमेंबरेंसर द्वारा कुछ अतिव्यापी मार्गों को अधिसूचित नहीं किए जाने से पहले भेदभाव के आधार पर योजना को चुनौती दी। उन्होंने माना कि भले ही इन मार्गों को मसौदा योजना में निर्दिष्ट नहीं

किया गया था और परमिट धारकों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, फिर भी इन मार्गों के संबंध में परमिट को अप्रभावी बनाने के लिए उनके पास खुला था और मैंने तदनुसार आदेश पारित किए। लीगल रिमेंबरेंसर के आदेश से प्रभावित परमिट धारकों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने लीगल रिमेंबरेंसर को इस मामले में फिर से जाने और बारह आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्गों के प्रश्न को बाद की योजना के लिए छोड़ने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में विचार किए गए लीगल रिमेंबरेंसर के निर्णय का प्रभाव यह हुआ कि सभी बारह आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्ग योजना से बाहर हो गए और केवल ड्राफ्ट-स्कीम में अधिसूचित तीन मार्ग प्रभावित हुए। वर्तमान याचिका उनके द्वारा संशोधित और 31 अगस्त, 1962 को प्रकाशित योजना को मंजूरी देने के उनके फैसले के खिलाफ निर्देशित है। इस न्यायालय में यह आग्रह किया गया था कि (1) योजना के एक हिस्से को एक बार और दूसरे हिस्से को बाद में मंजूरी देने की प्रक्रिया अवैध थी; (ii) कि कानूनी सलाहकार द्वारा अपने फैसले के त्याग के बाद योजना की मंजूरी वैध मंजूरी नहीं थी; (iii) कि लीगल रिमेंबरेंसर को शुरू से ही आपत्तिकर्ताओं को नए सिरे से सुनवाई का मौका देना चाहिए था; (iv) कि कोई उचित सुनवाई नहीं हुई और (v) कि भेदभाव हुआ, क्योंकि बारह आंशिक रूप से ओवरलैपिंग राउटर के ऑपरेटरों को योजना से बाहर रखा गया था।

अभिनिर्धारित किया कि चूँकि बारह अतिव्यापी मार्गों को कभी भी मसौदा योजना में शामिल नहीं किया गया था, इन मार्गों को छुए बिना मसौदा योजना को दी गई मंजूरी को योजना के एक हिस्से की मंजूरी नहीं कहा जा सकता है।

आगे अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का आदेश रिमांड आदेश के समान था और इसलिए, कानूनी सलाहकार के निर्णय को एक नया

निर्णय माना जाना चाहिए न कि उसके पिछले निर्णय की समीक्षा के रूप में उसके कार्यों के बारे में, और इसमें कोई त्याग नहीं था।

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया कि जब आपत्तिकर्ताओं को पिछले अवसर पर सबूत पेश करने का पूरा मौका दिया गया था, जो अभी भी कानूनी स्मरणकर्ता के ध्यान में रखने के लिए मौजूद था, तो उसके लिए आपत्तिकर्ता के तर्कों को सुनना पर्याप्त था। यदि यह ध्यान में रखा जाता है कि कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक रेनमांड आदेश की प्रकृति में था, तो यह आपत्ति विफल होनी चाहिए।

आगे अभिनिर्धारित किया कि तथ्य यह है कि नियमों में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किसी कठोर प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसके बिना उचित सुनवाई नहीं हो सकती है।

आगे, यह अभिनिर्धारित किया कि धारा के अंतर्गत धारा 68 सी राज्य सरकार के लिए किसी भी क्षेत्र या मार्ग को पूर्ण या आंशिक रूप से बाहर करने के लिए खुला था और वर्तमान मामले में पूरी तरह से कवर किए गए मार्गों के लिए कोई भेदभाव नहीं था, एक अलग मार्ग पर ले जाया गया मार्ग मार्गों से पैदल चलना केवल आंशिक रूप से कवर किया गया।

मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका संख्या 142/1962

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारत के संविधान की याचिका अनुच्छेद 32 के तहत।

याचिकाकर्ताओं की ओर से बी छंगुनी और डी शर्मा।

उत्तरदाताओं के लिए सी.के. दफ्तरी, भारत के सॉलिसिटर-जनरल, -कान सिंह, एस.के. कपूर और पी.डी. मेनन।

न्यायालय का निर्णय वांचू, जे. द्वारा 14 दिसंबर 1962 को सुनाया गया।

संविधान की अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका के तहत अंतिम रूप दी गई योजना की संवैधानिकता को चुनौती देती है। राजस्थान राज्य में मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की संख्या IV की धारा 68 डी (3), (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित)। याचिकाकर्ता, जोधपुर-बिलाड़ा और बिलाड़ा-ब्यावर मार्गों पर स्टेज-कैरिज परमिट के धारक हैं। एस के तहत एक मसौदा योजना प्रकाशित की गई थी। राजस्थान रोडवेज, जो कि एक राज्य परिवहन उपक्रम है, द्वारा अधिनियम की धारा 68 सी, (इसके बाद सड़क के रूप में संदर्भित), 26 जनवरी, 1961 को। इसमें जोधपुर-बिलाड़ा: ब्यावर पर परिवहन सेवा को संभालने का प्रावधान था। रोडवेज द्वारा अजमेर मार्ग। इसके अलावा इसमें तीन अतिव्यापी मार्गों या उसके हिस्सों को लेने का प्रावधान किया गया था जो पूरी तरह से जोधपुर-बिलाड़ा-ब्यावर-अजमेर रोड पर थे, अर्थात्, जोधपुर-बिलाड़ा, बिलाड़ा ब्यावर और ब्यावर अजमेर, और आर की आवश्यकता के अनुसार। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास) नियम, 1960, (बाद में नियमों के रूप में संदर्भित) के 3 में, इन तीन ओवरलैपिंग मार्गों पर परमिट धारकों के नाम उनके परमिट के साथ रद्द करने के लिए भी निर्दिष्ट किए गए थे, और इसके अलावा कोई परिवहन वॉलिकल नहीं था सड़क के वाहन. जिस मार्ग पर कब्जा किया जाना था उस पर रास्ते चलने थे। उन सभी लोगों को आपत्तियां दाखिल करने के लिए सामान्य समय भी दिया गया जिनके हित मसौदा योजना से प्रभावित हुए थे। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 68 डी के तहत आपत्तियां दायर कीं, जिनकी सुनवाई राजस्थान सरकार के कानूनी सलाहकार द्वारा की गई, वह आपत्तियों को सुनने और निर्णय लेने के लिए नियुक्त व्यक्ति थे। आपत्तिकर्ता सबूत पेश करना चाहते थे और उन्होंने कुछ गवाह पेश किए लेकिन कुछ गवाह पेश किए गए। जिन्हें समन जारी किया गया था वे उपस्थित नहीं हुए और आपत्तिकर्ता उनके विरुद्ध बलपूर्वक कार्यवाही का मुद्दा चाहते थे।

हालाँकि, लीगल रिमाइनर्सेस ने इस आधार पर इससे इनकार कर दिया कि उसके पास जबरदस्ती प्रक्रिया जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। चूंकि आपत्तिकर्ताओं ने कोई और गवाह पेश नहीं किया, इसलिए दलीलें सुनी गईं और लीगल अनुस्मारक ने 31 मई, 1962 को अपने फैसले दिए।

लीगल अनुस्मारक के समक्ष उठाए गए मुख्य बिंदुओं में से एक यह था कि एक दर्जन अन्य ओवरलैपिंग मार्ग थे जिन्हें योजना से नहीं छुआ गया था, और इसलिए यह योजना भेदभाव के आधार पर खराब थी। यह उल्लेख किया जा सकता है कि ये ओवरलैपिंग मार्ग राष्ट्रीयकृत होने वाले मार्ग को पूरी तरह से ओवरलैप नहीं कर रहे थे, हालाँकि उन बारह मार्गों पर चलने वाले वाहनों को जोधपुर-बिलाड़ा-ब्यावर-अजमेर रोड के हिस्से से गुजरना पड़ता था। रोडवेज की ओर से लीगल-रिमेंबर्सेस के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि इरादा इन बारह मार्गों पर परमिटों को अप्रभावी बनाने का था, क्योंकि वे उस मार्ग को ओवरलैप कर रहे थे जिसे लिया जाना था, हालाँकि इन मार्गों का मसौदा-योजना में उल्लेख नहीं किया गया था। तीन मार्ग जो पूरी तरह से जोधपुर-बिलाड़ा-ब्यावर अजमेर मार्ग द्वारा कवर किए गए थे और इन बारह आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्गों पर बहतर परमिट धारकों को स्पष्ट रूप से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। लीगल अनुस्मारक ने माना कि भले ही इन मार्गों को ड्राफ्ट-स्कीम में निर्दिष्ट नहीं किया गया था और परमिट धारकों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, फिर भी इन मार्गों के संबंध में परमिट को अप्रभावी बनाने के लिए उनके पास खुला था और पारित करने के लिए आदेश लापरवाही से आगे बढ़े।

इसके बाद ड्राफ्ट-स्कीम में अधिसूचित तीन मार्गों पर परमिट धारकों द्वारा और साथ ही आंशिक रूप से ओवरलैप होने वाले बारह मार्गों के कुछ परमिट धारकों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में पांच रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें लागू नहीं किया

गया था। अधिसूचित किया गया था लेकिन जो किया गया था। लीगल अनुस्मारक के आदेश से प्रभावित, 16 जून, 1963 को प्रकाशित योजना की वैधता को चुनौती के समर्थन में उच्च न्यायालय के समक्ष दो मुख्य बिंदुओं पर आग्रह किया गया था। सबसे पहले, यह आग्रह किया गया था कि योजना को प्रकाशित करते समय राज्य सरकार एस की आवश्यकता के अनुसार। अधिनियम के 08 डी (3) ने कानूनी सलाहकार के निर्णय से परे इसमें कुछ बदलाव किए थे और इसलिए प्रकाशित अंतिम योजना अमान्य थी क्योंकि यह राज्य के लिए खुली नहीं थी। सरकार लीगल रिमेंबर सेर द्वारा अनुमोदित योजना में कोई भी बदलाव करेगी। दूसरे, बारह आंशिक रूप से अतिव्यापी मार्गों पर ऑपरेटरों की ओर से यह आग्रह किया गया था कि मसौदा योजना में अधिसूचित नहीं किया गया था कि जब उनके मार्ग मसौदा योजना में निर्दिष्ट नहीं किए गए थे तो यह उनके हितों को प्रभावित करने के लिए कानूनी सलाहकार के लिए खुला नहीं था। और उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। हाई कोर्ट ने इन दोनों दलीलों को स्वीकार कर लिया। उसकी राय थी कि राज्य सरकार कानूनी सलाहकार के निर्णय में कोई भी संशोधन करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी और चूंकि ऐसा किया जा चुका था इसलिए प्रकाशित अंतिम योजना अमान्य थी। यह भी माना गया कि बारह आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्गों को मसौदे में अधिसूचित नहीं किया गया था। योजना और परमिट के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उसके धारकों के संबंध में कोई भी आदेश पारित करना कानूनी प्राधिकारी के लिए खुला नहीं था। इसलिए इसने एस के तहत प्रकाशित योजना को रद्द कर दिया। अधिनियम की धारा 68 डी(3), अंत में, उच्च न्यायालय ने कहा कि जैसा कि योजना प्रकाशित की गई थी, वह कानूनी स्मरणकर्ता द्वारा अनुमोदित योजना नहीं थी और चूंकि कानूनी स्मरणकर्ता का निर्णय प्रकाशित होने पर अंतिम हो जाता है, इसलिए यह कानूनी स्मरणकर्ता के लिए अपने निर्णय को संशोधित करने के लिए खुला था।, भले ही उन्होंने इस पर हस्ताक्षर और उच्चारण

किया हो। इस प्रकार कानूनी स्मरणकर्ता को इस मामले में फिर से जाने और बारह आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्गों के प्रश्न को बाद की योजना के लिए छोड़ने का निर्देश दिया गया। एस के तहत प्रकाशित अंतिम योजना। अधिनियम की धारा 68 डी (3) को अलग रखा गया और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को निर्देश दिया गया कि जब तक इसे कानून के मुताबिक नियमित नहीं किया जाता तब तक इसे लागू न किया जाए।

इसके बाद मामला कानूनी सलाहकार के पास वापस चला गया, जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में मसौदा-योजना पर विचार किया और आगे की सुनवाई के बाद आपत्तियों का निपटारा किया। उनके निर्णय का मुख्य प्रभाव यह हुआ कि सभी 12 आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्गों को योजना से बाहर कर दिया गया और मसौदा-योजना में अधिसूचित केवल तीन मार्ग जो पूरी तरह से जोधपुर-बिलाड़ा-ब्यावर-अजमेर मार्ग द्वारा कवर किए गए थे, प्रभावित हुए। उनके द्वारा संशोधित योजना को मंजूरी देने वाले लीगल अनुस्मारक का निर्णय 31 अगस्त, 1962 को प्रकाशित किया गया था, और वर्तमान याचिका उस निर्णय के खिलाफ निर्देशित है।

लीगल अनुस्मारक के निर्णय को हमारे समक्ष निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा रही है:

(1) अधिनियम के तहत एक मसौदा-योजना को समग्र रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए और योजना के एक भाग को एक बार और दूसरे भाग को बाद में अनुमोदित करने की प्रक्रिया अवैध है, और इसलिए, मसौदा-योजना को दी गई मंजूरी लीगल अनुस्मारक के परिणामस्वरूप ऐप योजना को विफल नहीं कर पाता, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है।

(2) उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी 31 मई 1962 के अपने आदेश की समीक्षा करना लीगल रिमेंबरेंसर के लिए खुला नहीं था, और जहाँ तक लीगल रिमेंबरेंसर

ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ऐसा किया, उसने अपना त्याग कर दिया। निर्णय, और इसलिए अपने स्वयं के निर्णय के ऐसे परित्याग के बाद अनुमोदन, कानून में कोई अनुमोदन नहीं है।

(3) चूँकि 16 जून, 1962 को प्रकाशित योजना को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, यह कानूनी स्मरणकर्ता का कर्तव्य था कि वह आपत्तिकर्ताओं को शुरू से ही नए सिरे से सुनवाई दे, जो उसने नहीं किया, और इसलिए- उनके द्वारा योजना के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान किया गया

हाई कोर्ट के फैसले के बाद कानून में कोई मंजूरी नहीं है।

(4) सुनवाई के लिए साक्ष्य लेने की आवश्यकता होती है; लेकिन जैसा कि कानूनी स्मरणकर्ता ने गवाहों की उपस्थिति के लिए बाध्य करने में असमर्थता व्यक्त की, कानून द्वारा अपेक्षित कोई सुनवाई नहीं हुई, और इसलिए उचित सुनवाई के बिना मसौदा-योजना की मंजूरी कानून में कोई मंजूरी नहीं है।

(5) इसमें भेदभाव था क्योंकि बारह आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्गों के ऑपरेटरों को योजना से बाहर रखा गया था।

दोबारा. (1) एवं (2)।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मसौदा-योजना पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए और राज्य सरकार या उसके लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले उस पर सभी आपत्तियों पर निर्णय लिया जाना चाहिए, और अधिनियम में अनुमोदन की परिकल्पना नहीं की गई है योजना के एक भाग को एक बार लागू करना और उसे लागू करना और दूसरे भाग को बिना अनुमोदन के छोड़ देना और बाद में प्रवर्तन के लिए छोड़ देना। यह भी सच है कि अधिनियम कानूनी अनुस्मारक द्वारा एक बार दिए गए अनुमोदन की समीक्षा का प्रावधान नहीं करता है, हालांकि वह किसी

भी लिपिकीय गलती या अनजाने परिचियों को ठीक करने का हकदार हो सकता है जो उसके आदेश में हो सकती हैं। यह भी सच है कि आपत्तियों पर विचार करते समय कानूनी स्मरणकर्ता को किसी विशेष मसौदा-योजना से संबंधित कानून के प्रश्नों पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के अधीन अपने निर्णय का प्रयोग करना होता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि यह ऐसा मामला है जहां मसौदा-योजना को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी गई है और इसके दूसरे हिस्से को बाद में लेने के लिए बिना मंजूरी के छोड़ दिया गया है; न ही यह ऐसा मामला है जहां कानूनी स्मरणकर्ता ने अपने फैसले को त्याग दिया या अपने पिछले फैसले की समीक्षा की जब वह उच्च न्यायालय द्वारा धारा के तहत प्रकाशित योजना को रद्द करने के बाद मामले पर पुनर्विचार करने के लिए आगे बढ़ा। 16 जून 1962 को अधिनियम की धारा 68 डी(3)।

आइए देखें कि इस मामले में मसौदा-योजना का उद्देश्य क्या था। जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, जोधपुर-बिलाड़ा-ब्यावर अजमेर मार्ग को अपने अधिकार में लेने के लिए मसौदा-योजना प्रकाशित की गई थी। इसमें सभी तीन पूरी तरह से ओवरलैप होने वाले मार्गों, अर्थात् जोधपुर बिलाड़ा, बिलाड़ा-ब्यावर और ब्यावर-अजमेर मार्गों और जोधपुर-अजमेर से इस सड़क पर पूरी तरह से पड़ने वाले उसके कुछ हिस्सों को भी अपने कब्जे में लेने का प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट-स्कीम में आंशिक रूप से अतिव्यापी मार्गों को लेने के लिए कोई संकेत नहीं था, जिसके केवल कुछ हिस्से जोधपुर-बिलाड़ा-ब्यावर-अजमेर सड़क पर ओवरलैप थे। ये आंशिक रूप से ओवरलैप होने वाले मार्ग दो प्रकार के थे। कुछ मामलों में एक टर्मिनस जोधपुर-बिलाड़ा-ब्यावर-अजमेर रोड पर था जबकि दूसरा टर्मिनस इस रोड पर नहीं था। अन्य मामलों में, ओवरलैपिंग मार्गों के दोनों टर्मिनल इस सड़क पर नहीं थे, हालांकि मार्ग का एक हिस्सा इस सड़क पर पड़ता था। नियमों के नियम 3 में ऐसे सभी ओवरलैपिंग मार्गों को इंगित करने का प्रावधान है, जिन्हें प्रभावित करने का इरादा है और वर्तमान मामले में मसौदा योजना

केवल तीन मार्गों को इंगित करती है जो पूरी तरह से इस सड़क पर थे, अर्थात्, जोधपुर-बिलाड़ा, बिलाड़ा-ब्यावर, और ब्यावर-अजमेर, और अन्य ओवरलैपिंग मार्गों से बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, जहां ओवरलैपिंग केवल आंशिक थी। इसलिए हमारी राय में जब इस मसौदा योजना पर आपत्तियों पर विचार किया जा रहा था तो बारह आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्गों का प्रश्न लाना अनावश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस भ्रम की स्थिति के लिए रोडवेज भी जिम्मेदार था क्योंकि ऐसा लगता है कि जब पहली बार आपत्तियों पर विचार किया गया था, तो उसकी ओर से आग्रह किया गया था कि इन आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्गों को भी इसमें शामिल किया जाना था। मसौदा योजना, भले ही मसौदा योजना में उनका उल्लेख नहीं किया गया था जैसा कि आवश्यकता थी। नियमों के 3 और उन मार्गों के परमिट धारकों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इन ओवरलैपिंग मार्गों के संबंध में भी एक मुद्दा उठाया, और इस तरह पहले अवसर पर, लीगल रेमम ब्रेंसर ने माना कि भले ही ये मार्ग थे, मसौदा योजना में शामिल नहीं किया गया था और इसके परमिट धारकों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, उसके संबंध में आदेश पारित करने के लिए यह खुला था और वह इन मार्गों के अतिव्यापी हिस्से को अप्रभावी बनाने के लिए आगे बढ़ा। मसौदा योजना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन बारह आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्गों को इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया था और इन्हें केवल याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति और रोडवेज के जवाब के कारण लाया गया था कि वे इसके लिए बने थे। शामिल हो। इसीलिए जब उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं पर निर्णय लिया गया, तो उसने बताया कि योजना में आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्गों को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि लीगल रिमेंबरेंसर ने इन मार्गों को भी योजना में शामिल करना उचित समझा, तो उसे सभी संबंधित पक्षों को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए नोटिस देना चाहिए था। सम्मान

के साथ हमें ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट की यह टिप्पणी सही नहीं है. यदि योजना में आंशिक रूप से अतिव्यापी मार्गों को शामिल नहीं किया गया था - जैसा कि निस्संदेह नहीं था, इसके बावजूद कि आपत्तिकर्ताओं ने क्या कहा होगा और रोडवेज ने पहले अवसर पर लीगल रिमेंबरेंसर के समक्ष क्या रखा होगा - यह लीगल रिमेंबरेंसर के लिए खुला नहीं था। इन ओवरलैपिंग मार्गों को योजना में शामिल करने के लिए और वह ऐसा नहीं कर सका, भले ही उसने इन ओवरलैपिंग मार्गों पर परमिट धारकों को नोटिस दिया हो। इसलिए यह प्रश्न कि क्या 31 अगस्त 1962 को प्रकाशित मसौदा योजना की अंतिम मंजूरी केवल योजना के एक हिस्से की मंजूरी है, योजना के दूसरे हिस्से को अस्वीकृत छोड़ दिया गया है और इसलिए बाद में प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है, केवल एक ही उत्तर स्वीकार किया जा सकता है, अर्थात्, अनुमोदन समग्र रूप से योजना का था। इसलिए याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क कि योजना के एक हिस्से को मंजूरी दे दी गई है और बाकी को अस्वीकृत छोड़ दिया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई बल नहीं दे सकता है। बारह अतिव्यापी मार्ग कभी भी इस योजना से प्रभावित नहीं होने वाले थे, जिससे वे अछूते रह गए। विवाद यह है कि यह योजना का केवल एक हिस्सा रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अनुमोदन इस तथ्य पर आधारित है कि इन मार्गों को अप्रभावी नहीं बनाया गया है। अतिव्यापी भाग के रूप में, लेकिन चूंकि इन मार्गों को कभी भी मसौदा योजना में शामिल नहीं किया गया था, इन परिस्थितियों में इन मार्गों को छुए बिना मसौदा योजना को दी गई मंजूरी को योजना के एक हिस्से की मंजूरी नहीं कहा जा सकता है। न ही हम यह सोचते हैं कि इस विवाद में कोई दम है कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद दूसरे अवसर पर प्रश्न पर विचार करते समय लीगल रिमेंबरेंसर ने अपना फैसला छोड़ दिया। 17 अगस्त, 1962 के लीगल रिमेंबरेंसर के आदेश से पता चलता है कि उन्होंने आगे की दलीलें सुनने के बाद पूरे मामले पर

पुनर्विचार किया और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि जब उन्होंने अंततः कुछ संशोधनों के साथ मसौदा योजना को मंजूरी देने का फैसला किया तो वह अपने फैसले का प्रयोग कर रहे थे। इस मामले में लीगल रिमेंबरेंसर ने जो किया है वह उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई कानूनी स्थिति के आलोक में सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करना है। न ही हम यह सोचते हैं कि इस तर्क में कोई दम है कि 17 अगस्त, 1962 का लीगल रिमेंबरेंसर का आदेश, उनके 31 मई, 1962 के पहले के आदेश की समीक्षा है। जब उच्च न्यायालय ने 16 जून, 1962 को प्रकाशित अंतिम योजना को रद्द कर दिया तो वास्तव में इसे रद्द कर दिया गया। यह सच है कि उस प्रकाशन ने लीगल रिमेंबरेंसर द्वारा अनुमोदित योजना में कुछ और संशोधन किए, लेकिन हमारी राय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तथ्य यह है कि 16 जून, 1962 को प्रकाशित अंतिम योजना को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश ने 31 मई, 1962 के लीगल रिमेंबरेंसर के आदेश को भी समाप्त कर दिया। समीक्षा के रूप में यह तर्क उच्च न्यायालय के फैसले में इस टिप्पणी के कारण उठाया गया है कि 16 जून, 1962 को अंतिम रूप से प्रकाशित योजना राज्य सरकार द्वारा इसमें किए गए परिवर्तनों के कारण कानूनी स्मरणकर्ता का निर्णय नहीं थी और इसलिए इसमें संशोधन करना उनके लिए खुला था, भले ही उन्होंने अपने निर्णय पर हस्ताक्षर करके उसे सुनाया हो। सम्मानपूर्वक हम मानते हैं कि यह अवलोकन सही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि राज्य सरकार के पास लीगल रिमेंबरेंसर के निर्णय को संशोधित करने का केनो अधिकार था, लेकिन जब उच्च न्यायालय ने 16 जून, 1962 को प्रकाशित अंतिम रूप से अनुमोदित योजना को रद्द कर दिया, तो इसका मतलब 31 मई को लीगल रिमेंबरेंसर का निर्णय था। 1962 भी समाप्त हो गया, क्योंकि 16 जून 1962 को प्रकाशित अंतिम योजना निस्संदेह इसी पर आधारित थी, भले ही प्रकाशन के समय उस निर्णय में और भी बदलाव हुए थे। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का आदेश रिमांड के समान था जैसा कि कानून की अदालतों में समझा

जाता है। दूसरे अवसर पर लीगल रिमेंबरेंसर ने जो किया वह उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करना था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि 17 अगस्त, 1962 को लीगल रिमेंबरेंसर का निर्णय, 31 मई, 1962 के उनके पहले के फैसले की समीक्षा है। उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम फैसले को रद्द करने के बाद, इसे एक नया निर्णय माना जाना चाहिए। योजना 16 जून, 1962 को प्रकाशित हुई। हालांकि इसलिए याचिकाकर्ताओं की ओर से रखे गए प्रस्ताव को सही माना जा सकता है, लेकिन इन प्रस्तावों में निहित सिद्धांतों को इस मामले के तथ्यों पर लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए यह तर्क कि 31 अगस्त, 1962 को अंतिम रूप से प्रकाशित योजना खराब है क्योंकि यह इन सिद्धांतों के विरुद्ध है, इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

दोबारा. (3) एवं (4).

यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा 16 जून, 1962 को प्रकाशित अंतिम योजना को रद्द करने के बाद, लीगल रिमेंबरेंसर को शुरू से ही नए सिरे से सुनवाई करनी चाहिए थी और उन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे यह भी आग्रह किया गया है कि चूंकि नियमों में उन गवाहों की उपस्थिति के लिए बाध्य करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिन्हें कोई आपत्तिकर्ता पेश करना चाहता है, इसलिए आपत्ति की कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हो सकती है, और इसलिए 31 अगस्त, 1962 को अंतिम रूप से प्रकाशित योजना अमान्य है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद लीगल रिमेंबरेंसर ने आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई दी। हालाँकि आग्रह यह है कि लीगल रिमेंबरेंसर द्वारा आपत्तियों का अंतिम रूप से निपटान करने से पहले आपत्तिकर्ताओं को नए सिरे से साक्ष्य देने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। हमारी राय है कि यद्यपि उच्च न्यायालय के आदेश का परिणाम 31 मई, 1962 के लीगल रिमेंबर के आदेश को रद्द करना था,

लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के आदेश ने उन सबूतों को मिटा दिया जो आपत्तिकर्ताओं के पास थे। प्रथम अवसर पर कानूनी अनुस्मारक के समक्ष दिया गया। हम पहले ही उन दो आधारों का उल्लेख कर चुके हैं जिन पर उच्च न्यायालय ने 16 जून, 1962 को प्रकाशित अंतिम योजना को रद्द कर दिया था, और उन आधारों का उन सबूतों से कोई लेना-देना नहीं था जो पहले ही पेश किए जा चुके थे। हमारी राय में, उस साक्ष्य को ध्यान में रखना कानूनी स्मरणकर्ता के लिए खुला था और यह आवश्यक नहीं था कि साक्ष्य दोबारा दिया जाए, खासकर जब कोई नया मुद्दा न उठा हो; न ही लीगल रिमेंबरेंसर नए साक्ष्य लेने के लिए बाध्य था, क्योंकि 16 जून, 1962 को प्रकाशित अंतिम योजना को कुछ तकनीकी और कानूनी दोषों के कारण रद्द कर दिया गया था। जब आपत्तिकर्ताओं को पिछले अवसर पर सबूत पेश करने का पूरा अवसर दिया गया था, जो अभी भी लीगल रिमेंबरेंसर के लिए मौजूद था, तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद लीगल रिमेंबरेंसर के लिए आपत्तिकर्ताओं की दलीलें पूरी तरह से सुनना पर्याप्त था। इसके द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में, और याचिकाकर्ताओं को इस बात पर कोई शिकायत नहीं हो सकती है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। यदि यह ध्यान में रखा जाए कि कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रिमांड आदेश की प्रकृति में था, तो ये सभी आपत्तियाँ स्पष्ट रूप से निराधार होंगी।

इस तर्क के संबंध में कि नियम गवाहों की उपस्थिति के लिए बाध्य करने का प्रावधान नहीं करते हैं और कानूनी स्मरणकर्ता जो कुछ भी कर सकता है वह उन गवाहों को बुलाना है जो सम्मन के उत्तर में उपस्थित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, यह कहना पर्याप्त है कि अर्धन्यायिक होते हुए भी कानूनी अनुज्ञप्तिकर्ता के समक्ष कार्यवाही बिल्कुल अदालत में कार्यवाही की तरह नहीं है। इस प्रकार की कार्यवाहियों में, जब किसी गवाह को बुलाया जाता है और वह उपस्थित नहीं होता है, तो यह निष्कर्ष

निकाला जा सकता है कि वह साक्ष्य नहीं देना चाहता है, और यही कारण हो सकता है कि नियमों में किसी भी दंडात्मक प्रक्रिया के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम सोचते हैं कि कानूनी स्मरणकर्ता द्वारा दी जाने वाली सुनवाई की परिस्थितियों में, यह पर्याप्त है यदि वह उन गवाहों का साक्ष्य लेता है जिन्हें आपत्तिकर्ता स्वयं उसके सामने लाते हैं और यदि वह उन्हें सम्मन जारी करके उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद करता है। लेकिन तथ्य यह है कि नियम ज़बरदस्ती प्रक्रियाओं के लिए प्रावधान नहीं करते हैं, कानूनी अनुस्मारक के समक्ष सुनवाई की विशेष परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी ज़बरदस्त प्रक्रियाओं के बिना कोई उचित सुनवाई नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी राय है कि लीगल रिमेंबरेंसर ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई दी और उन परिस्थितियों में सुनवाई उचित और पर्याप्त सुनवाई थी। इसलिए इस आधार पर 16 जून, 1902 को प्रकाशित योजना की वैधता को चुनौती को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

दोबारा. (5).

अंततः हम भेदभाव के प्रश्न पर आते हैं। यह तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि जिन बारह आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्गों का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। निस्संदेह ऐसा ही है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इन मार्गों की स्थिति में एक टर्मिनस जोधपुर बिलाड़ा-ब्यावर-अजमेर रोड पर है जबकि दूसरा इस रोड पर नहीं है। कुछ मामलों में कोई भी टर्मिनी इस सड़क पर नहीं है और मार्ग केवल इसका एक हिस्सा है जो इस सड़क को ओवरलैप करता है। तर्क यह है कि चूंकि इन आंशिक रूप से ओवरलैपिंग मार्गों पर परमिट-धारकों को इस योजना से नहीं छुआ गया है, इसलिए भेदभाव है क्योंकि तीन मार्गों पर परमिट-धारक जो उस मार्ग को पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे थे जिसे लिया जा रहा था, उन्हें पूरी तरह से

हटा दिया गया है। छोड़ा गया। हमें नहीं लगता कि यह भेदभाव है। यह बताया जा सकता है कि एस के तहत। 68 सी किसी भी क्षेत्र या मार्ग को अन्य व्यक्तियों के पूर्ण या आंशिक बहिष्कार के लिए अपने अधिकार में लेने के लिए खुला है। इसलिए, यह राज्य सरकार के लिए खुला था कि वह केवल इस मार्ग को अपने अधिकार में ले और उन लोगों को बाहर कर दे जो इस मार्ग या इसके कुछ हिस्सों पर पूरी तरह से यात्रा कर रहे हों और जब तक यह नहीं दिखाया जा सके कि अन्य जो इसी तरह स्थित हैं, उन्हें योजना से बाहर नहीं किया गया है। भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। हमारी राय में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे परमिट-धारक जिनके मार्ग पूरी तरह से लिए गए मार्ग से कवर किए गए थे, उन लोगों के समान ही हैं जिनके मार्ग केवल आंशिक रूप से लिए गए मार्ग से कवर किए गए थे। यह बहुत अच्छी तरह से माना जा सकता है कि पहली बार में केवल उन परमिट-धारकों को बाहर रखा जाएगा जिनके मार्ग पूरी तरह से अधिग्रहित मार्गों द्वारा कवर किए गए हैं, और यदि यह कानून के तहत स्वीकार्य है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह भेदभावपूर्ण राष्ट्र होगा जब लिए जाने वाले मार्ग द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए मार्गों और लिए जाने वाले मार्ग द्वारा आंशिक रूप से कवर किए गए मार्गों के बीच स्पष्ट अंतर होता है। हमें सूचित किया गया है कि इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद से उन परमिट धारकों को बाहर करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं जिनके मार्ग आंशिक रूप से कवर किए गए हैं, जिससे मार्ग के ओवरलैपिंग हिस्से पर उनके परमिट अप्रभावी हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा, हम वर्तमान मामले में भेदभाव की दलील को बरकरार रखने के लिए कोई आधार नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जिन मार्गों को पूरी तरह से कवर किया गया है, वे केवल आंशिक रूप से कवर किए गए मार्गों से अलग पायदान पर खड़े हैं। इसलिए विवाद यह है कि अंतिम योजना। जैसा कि 31 अगस्त, 1962 को प्रकाशित हुआ था, खराब है क्योंकि यह इस तरह से भेदभाव करता है, इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

इसलिए हम याचिका खारिज करते हैं लेकिन इस मामले की परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करते हैं।

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।